



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 2 अगस्त, 1997

श्रावण 11, 1919 शक सन्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग - 1

संख्या 1126/सत्रह-वि-1-1 (क) 28/1997

लखनऊ, 2 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 पर दिनांक 2 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें,

2—इस अधिनियम में,—

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है;

(ख) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(ग) "राष्ट्रीय महिला आयोग" का तात्पर्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग से है;

(घ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है;

(ङ) "महिला" में बालिका या किशोरी सम्मिलित हैं।

अध्याय—दो

राज्य महिला आयोग

आयोग का गठन

3—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित कोई विख्यात व्यक्ति होगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट छः से अनाधिक सदस्य जो अधिमानतः महिलायें हों और जिन्होंने महिलाओं के हित के लिए सेवा की हो या जिन्हें विधि या विधायन में या महिलाओं की उन्नति से संबंधित मामलों के प्रशासन में या महिलाओं के हितों के संरक्षण, उत्थान या उन्नयन के लिए महिलाओं के किसी ट्रेड यूनियन या स्वैच्छिक संगठन के नेतृत्व का, पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो:

परन्तु उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

पदावधि और सेवा की शर्तें

4—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दण्डित किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गर्त है;

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाए ।

5—(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों ।

आयोग के अधिकारी, और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं ।

6—अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा ।

वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना

7—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी

8—(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा ।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा ।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य

9—(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् :-

आयोग के कृत्य

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्ता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ड) महिलाओं से संबंधित संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित मामलों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेना :-

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों से उद्भूत विवादों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे कि आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी उवाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकेतों को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी/कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलायें कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

10—किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उपखण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और
- (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय-चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

11—(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे। राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा।

12—(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा। लेखा और लेखा, परीक्षा

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी।

13—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा। वार्षिक रिपोर्ट

14—राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी। राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

15—आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थात्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

16—राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

17—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

18—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य विषय;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

19—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1126 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 28-1997

Dated Lucknow, August 2, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Aayog Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 1997.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN ACT, 1997

(U.P. ACT NO. 7 OF 1997)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to establish a State Commission for women and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the forty-eighth year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
commence-
ment

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act,—

Definitions

(a) "Commission" means the Uttar Pradesh State Commission for Women constituted under section 3 ;

(b) "Member" means a member of the Commission ;

(c) "National Commission for Women" means the National Commission for Women constituted under section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 ;

(d) "Other Backward Classes of citizens" means such classes of citizens as are defined in clause (b) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 ;

(e) "Women" includes female-child or adolescent girl.

CHAPTER II

THE STATE COMMISSION FOR WOMEN

3. (1) The State Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Uttar Pradesh State Commission for Women to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

Constitution of the Commission

(2) The Commission shall consist of—

(a) Chairperson who shall be an eminent person committed to the cause of women to be nominated by the State Government ;

(b) Not more than six Members preferably women, to be nominated by the State Government from amongst the persons of ability, integrity and standing who have served the cause of women or have had sufficient knowledge and experience in law or legislation, administration of matters concerning the advancement of women or leadership of any trade union or voluntary organisation for women, for protection, upliftment and promotion of interests of women ;

Provided that, at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other Backward Classes of citizens, respectively ;

(c) A Member-Secretary, to be nominated by the State Government who shall be a women officer, not below the rank of a Special Secretary to the State Government, who is a member of a civil service of the State or of an All India Service or holds a civil post under the State with appropriate experience.

4. (1) The Chairperson and every Member shall hold office for a period of three years from the date he assumes office.

Term of office and conditions of service

(2) The Chairperson or a Member other than the Member-Secretary may, by writing under his hand and addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of chairperson or a Member if that person—

(a) becomes an undischarged insolvent ;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment.

for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) in the opinion of the State Government, has so abused the position of the Chairperson or Member as to render that persons continuance in office detrimental to the public interest or is otherwise unfit or unsuitable to continue as such Chairperson or Member :

Provided that, no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries, and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of Commission

5. (1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of, the Member-Secretary, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the Member Secretary, the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 11.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of Commission
Procedure to be regulated by Commission

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary and at such time and place, as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member-Secretary in this behalf.

CHAPTER III FUNCTIONS OF THE COMMISSION

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:—

(a) investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws;

(b) present to the State Government, annually and at such other times, as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

ber
acti
non

(c) make in such reports recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women by the State;

(d) review, from time to time, the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or shortcomings in such legislations;

(e) take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to women with the appropriate authorities;

(f) look into specific complaints and take *suo motu* notice of matters relating to.—

(i) deprivation of women's rights;

(ii) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality and development;

(iii) non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women.

and to take up the issues arising out of such matters with the appropriate authorities;

(g) cause special studies or investigations to be undertaken into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constraints so as to recommend strategies for their removal;

(h) undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and identify factors responsible for impeding their advancement, such as, lack of access to housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their productivity;

(i) participate and advise on the planning process of socio-economic development of women;

(j) evaluate the progress of the development of women under the State;

(k) inspect or cause to be inspected a jail, remand home, women's institution or other places of custody where women are kept as prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities for remedial action, if found necessary;

(l) fund litigation involving issues affecting a large body of women or the interpretation of any provision of the Constitution or any other laws affecting women;

(m) make periodical or special reports to the State Government on any matter pertaining to women and, in particular, various difficulties under which women toil;

(n) any other matter which may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each house of the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Powers of the
Commission

10. The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or sub-clauses (i) and (ii) of clause (f) of sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit, and in particular, in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;
and

(f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants by
the State
Government

11. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and
Audit

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) A copy of the annual statement of accounts shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

Annual report

13. The commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed, giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual and
other reports
and audit report
to be laid
before State
Legislature

14. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations, and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received, before each House of the State Legislature.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

Chairperson,
Members and
staff of Com-
mission to be
public servants

15. The Chairperson, the Members, the Member-Secretary, officers and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

State
Government to
consult
Commission

16. The State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting women.

17. No. suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder. Protection of action taken in good faith

18. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Such rules may provide for charging of fees for any of the purposes of this Act. Power to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) Salaries, and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of section 4 and the Member-Secretary, the officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(b) any other matter under clause (f) of section 10;

(c) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 12;

(d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 13;

(e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

19. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulty

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

By order,

R.D. MATHUR,

Pramukh Sachiv.